सैनिकों की पैंशन की दरें बढ़ाने के बारे में जो निरुचय ३१ दिसम्बर, १९६० को किया गया था, उसे किपान्वित करने की दिशा में इस बीच क्रौर क्या प्रगति हुई है क्रौर क्रब तक प्रत्येक राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पेंशनों की बढ़ी हुई दरों का लाभ वास्तव में पहुंचाया जा चुका है ?

प्रतिरका मंत्री (थी कृष्ण मेनन) : ३१ मक्तूबर, १९६१ को समाप्त होने वाले त्रिमास में. प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद ने, लगभग ३४,००० म्रलग झलग मामलों में, पेंशन में भस्थायी वद्धियों में बढोतरो की स्वीकृति दी है। त्रिमास के मन्त में. ४८.००० म्रधिक म्रलग म्रलग मामले. उस कार्यालय में निरीक्षण के विभिन्न स्तरों पर थे। वास्तविक ग्रदायगी, इन मलग मलग स्वीकृतियों, भौर पेंशन के कूछ वर्गों से संबद्ध, प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद की, पहले जारी की मई, साधारण स्वीकृतियों के बल पर, पेंशनों का भगतान करने वाले मधिकारियों द्वारा देश भर में की जारही हैं, भीर की जाती रहेगी। इन स्वीकृतियों के प्रति, की गई वास्तविक भदायगियों की स्थिति, २३ नवम्बर, १९६१ को उत्तर दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर में दर्शाई गई थीं।

२. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में, प्रस्थायी वृद्धियों की दरों में बढ़ोतरी के बारे में, सरकार के निर्णयों को लागू करने में, प्रगति के ग्रांकड़े, ग्राखिल भारतीय प्राघारों पर रखे जाते हैं, ग्रीर इस बारे में, राज्यवार त्रोट-मांकड़े सहज सुलभ नहीं हैं।

Board of Control for Cricket in India

1594. Shri Indrajit Gupta: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the All-India Council of Sports has levelled serious

.

charges against the Board of Control for Cricket in India;

(b) whether it is a fact that the Board has denied all charges and challenged the authority of the A.I.C.S. to inquire into the Board's affairs; and

(c) Government's reaction in the matter?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir. The All-India Council of Sports through a Sub-Committee only enquired into certain allegations made against the Board of Control for Cricket in India in the Press and in the Parliament, without actually levelling any charge against the Board.

(b) No, Sir. The question does not arise as no charges had been levelied at any time. However, the Board resented the appointment of the Enquiry Committee, as it presumably felt that the enquiry might lead to an unnecessary interference in their autonomy. Even so, representatives of the Board did meet the members of the Committee and apprised them of the Board's views with regard to the various allegations.

(c) The All India Council of Sports has taken note of the assurance given by the Board that it will only be too willing to receive and implement constructive suggestions.

Bhilai Steel Plant

1595. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Steel, Mines and Fuel be pleased to state:

(a) whether a particular union at Bhilai Steel Plant has submitted a detailed memorandum containing certain grievances of the workers;

(b) if so, what are those grievances; and

(c) steps taken to redress such grievances?

The Minister of Steel, Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh): (a) Yes, Sir. An unrecognised Union at